

सुरक्षा चूक के मामले पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, दोनों सदन सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

पानी व खाने में बढ़ते प्लास्टिक के अंश पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताई चिंता

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर संसद में हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर शुक्रवार को भी जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य सुरक्षा चूक के मामले पर सदन में गुहमंजी अमित शाह के वक्तव्य और चर्चा की मांग कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठसीन सभापति किरिट सोलंकी ने कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए अंतिम स्थगित कर दी। इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। विपक्ष के सांसद इस मुद्दे पर गुहमंजी अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। कुछ सदस्यों के हाथों में पोस्टर भी थे। एक पोस्टर पर संसद में सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग लिखी हुई थी। कुछ सदस्य गुहमंजी शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। कुछ विपक्षी सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफकार्रवाई की भी मांग कर रहे थे, जिनके हस्तक्षर से मिले 'पास पर संसद भवन में प्रवेश करने वाले दो युवक कुश्तार को लोकसभा के दफ्तर दीर्घा से सदन में कूट गए थे। पीठसीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही सेकंड के भीतर अपराध दो बजे तक स्थगित कर दी। सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों



अगर संसद सुरक्षित नहीं है, तो क्या देश सुरक्षित है, राज्यसभा में बोले आप सांसद राघव चड्ढा

नई दिल्ली। जब हमारे देश में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में उल्लंघन हो रहा है तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है?...हालिया सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर संसद में चर्चा की मांग करते हुए आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को सवाल किया। राघव चड्ढा ने पूछा, क्या विपक्षी सांसद कुछ नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या वे कुछ गलत कह रहे हैं? वे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देश की सबसे सुरक्षित इमारत की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को मांग मान लेनी चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा, यह किसी विशेष पार्टी या पार्टी की राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद का मामला है। अगर संसद सुरक्षित नहीं है, तो क्या देश सुरक्षित है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सुझाव मांगे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें सुधार के लिए सुझाव देना चाहिए। वे बाधाएं पैदा करके कुछ हासिल नहीं करेंगे। इस बीच, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार सभी चार आरोपियों को सात दिन की हिरासत में भेज दिया। पांचवें आरोपी ललित झा को भी दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद में बयान देना चाहिए था, जिससे पूरा संकट सुलझ सकता था।

ने बृहस्पतिवार को भी सदन में हंगामा किया था। सदन में आसन की अवमानना और अनाद

लोकसभा सुरक्षा में सेंध के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

नई दिल्ली। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के कथित मास्टरमाइंड ललित झा ने गुरुवार रात दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जांच से जुड़े अधिकारियों ने आईएनएस को फेन पर यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा, झा, झा हमारी हिरासत में हैं। हम उससे पूछताछ के बाद और जानकारी साझा करेंगे। झा ने नयी दिल्ली जिले के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एक सूत्र ने कहा, आगे की जांच के लिए उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को, इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार मुख्य आरोपियों - सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद और अमोल शिंदे को दिल्ली की एक अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मनोरंजन मैसूर का रहने वाला, जबकि सागर लखनऊ का, नीलम हरियाणा के जिला की रहने वाली है, जबकि अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उनके और बिहार के मूल निवासी झा के खिलाफ दर्ज मामले में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (लोक सेवकों के काम में बाधा डालना), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवकों को कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूपीए) की धारा 16 और 18 लगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, पांचों मुख्य आरोपियों ने कथित तौर पर घटना से पहले रात गुरुग्राम के सेक्टर 7 में विक्रम उर्फ विक्की शर्मा नाम के व्यक्ति के आवास पर बिताई थी। वे बुधवार सुबह 8 बजे घर से निकले थे। मामले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए विक्रम और उसकी पत्नी राखी को घंटों पूछताछ के बाद गुरुवार शाम को जाने दिया गया। एक सूत्र के अनुसार, झा ने अपनी योजना को अंजाम देने से ठीक पहले चार अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन ले लिए और जल्दबाजी में भाग निकला। झा ने कथित तौर पर संसद के बाहर अमोल और नीलम के विरोध प्रदर्शन को भी पिछमाया और इसे नीलकण्ठा आइच नाम के एक व्यक्ति के साथ साझा किया, जो पश्चिम बंगाल में एक एनजीओ (सामोवादी सुभाष) से जुड़ा हुआ है।

लोकसभा में कांग्रेस के वीके श्रीकंदन, बेनी बेहन, मोहम्मद जावेद, मणिकम टैगोर, टी एन प्रताप, हथो डंडेन, जेतिमिंग, रम्या हरिदस और डीन कुरियाकोस, द्रमुक की किर्नोई, सदस्यों को मौजूद शीतकालीन सत्र की शेष मुनेत्र कणम (द्रमुक) समेत विपक्ष के 13 अवधि के लिए निर्वाचित कर दिया गया।

खबरें एक नजर में

अभी भी आईसीयू में है एक्टर श्रेयस तलपड़े

मुंबई। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को दिल का दौरा पड़ा है और मुंबई में उनकी एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई है। अस्पताल के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। श्रेयस (47) ने वीरवार को बेचौनी की शिकायत की थी और वह अपने घर में बेहोश हो गए थे। उनके परिवार के सदस्य उन्हें अंधेरी के बेलेव्यू हॉस्पिटल लेकर गए थे। इससे पहले गुरुवार शाम वह फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। श्रेयस उस समय पूरी तरह स्वस्थ और फिट थे। अभी उनकी हालत स्थिर है और वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं, अस्पताल के मुताबिक उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। अस्पताल के अधिकारी ने कहा, "उन्हें देश शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया और दो रात उनकी एंजियोप्लास्टी की गयी। वह ठीक हैं। वह आईसीयू में हैं। मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, तलपड़े अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग से बृहस्पतिवार को घर लौटे थे। उनके परिवार के एक सदस्य ने बताया कि अभिनेता स्वस्थ हो रहे हैं और उन्होंने मीडिया से निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "वह ठीक हैं। वह पहले से बेहतर हैं। हम आपसे निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। हिंदी और मराठी सिनेमा में काम कर चुके श्रेयस को "इकबाल", "डेर", "ओम शांति ओम" और "गोलमाल श्रृंखला की फिल्मों में उनके अभिनय के लिए पहचाना जाता है।

सजा सुनते ही फूट-फूट कर रोना लगा बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़, दुष्कर्म मामले में मिली 25 साल की सजा

सोनभद्र। सोनभद्र की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को दुई विधानसभा क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट) से भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को एक नाबालिग लड़की से 9 साल पहले बलात्कार करने के मामले में 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। एमपी, एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ए डी जे) एहसान उल्लेख खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, सजा सुनते ही विधायक रामदुलार गौड़ फूट-फूट कर रोने लग गया। विशेष लोक अभियोजक (पब्लिक) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने 12 दिसंबर को विधायक को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी। फैसला सुनाए जाने से पहले गौड़ के वकील ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया और अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि बलात्कार पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल आरोपी द्वारा की जाएगी। गौड़ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना चार नवंबर 2014 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के समय विधायक की पत्नी गम प्रधान थी। इस मामले में रामदुलार गौड़ को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बताया गया था। पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपु थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया था। गौड़ उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी। गौड़ के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद विधायक (एमपी, एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई।

बर्तन और पकौड़े लेकर आया विपक्ष, राज्य सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन

नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के छठे दिन विपक्षी दलों के नेताओं ने बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। महा विकास आघाड़ी गठबंधन के विधायक शुक्रवार को विधान भवन की सड़ियों पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस गठबंधन में शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रकापा) का शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधायक सतेज पाटिल और सचिन अहिर समेत अन्य नेता बर्तन और पकौड़े लेकर आए। पत्रकारों से बात करते हुए दानवे ने दावा किया कि राज्य में बेरोजगारी युवाओं की संख्या बढ़ी है।

नीतीश ने नवादा में गंगाजल आपूर्ति योजना का किया लोकार्पण, हर घर तक पहुंचा शुद्ध पेयजल के रूप में गंगाजल

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा जिला के कादिरांज के पौरा गांव में गंगाजल आपूर्ति योजना का शिलापट्ट अनावरण कर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 36 मिलियन लीटर विलयन वाटर पंप हाउस का बटन दबाकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जल शोधन संयंत्र का अवलोकन किया। इस दौरान जल शोधन संयंत्र के अवलोकन के अवसर परी सेंट्रलिंग टैंक, कैस्केड एरियटर, फ्लैश मिक्सचर, क्लैरी फ्लो कुलेटर एवं फिल्टर यूनिट के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जल शोधन केंद्र परिसर में पौधा रोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंगाजल आपूर्ति योजना के कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अब गंगाजी राजगृह जलाशय से लगभग 20 किलोमीटर पाईप लाईन बिछकर नवादा के



पौरा में जल-शोधन संयंत्र तक गंगाजल को पहुंचाया जा रहा है। जहां से नवादा शहर के घर-घर में बुडको (नगर आवास एवं विकास विभाग) द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। पौरा (नवादा) के इस जन-शोधन संयंत्र में 36 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी को साफ करने की क्षमता है। वहीं पर एक मास्टर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का निर्माण भी किया गया है। जिसमें 36 मिलियन लीटर पानी साफ करने के बाद रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर सर्वेक्षण का इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस बी एन भट्टी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ के समक्ष मस्जिद पक्ष की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता हुजुम अहमदी ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अदालत ने पहले कहा था कि मामले में सुनवाई की जरूरत है। इस मामले में हमसे लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा गया था। उन्होंने कहा,

"लेकिन अब हाईकोर्ट कुछ आवेदनों पर विचार कर रहा है, जिनके दृष्टांती परिणाम होंगे। इस पर पीठ ने कहा, "इस स्तर पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। यदि कोई प्रतिकूल आवेदन है तो आप यहां आ सकते हैं। अहमदी ने कहा कि गुरुवार को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें आयुक्त को शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने और इसके लिए आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा, "यह तब हो रहा है जब शीर्ष अदालत इस मामले में अधिकार क्षेत्र का फैसला कर रही है। पीठ ने अहमदी से हाईकोर्ट को यह बताने को कहा कि वह (शीर्ष अदालत) नौ जनवरी को मामले की सुनवाई करने वाली है। इस पर अहमदी ने दलील देते हुए कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। शीर्ष अदालत ने हालांकि, कहा कि उसके समक्ष एकमात्र अधिकार क्षेत्र का स्थानांतरण का मामला है। इस तरह मामला अब उसके समक्ष योग्यता के आधार पर नहीं है। पीठ ने कहा, "यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो वह कानून के अनुसार चुनौती दायर कर सकता है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। सर्वेक्षण किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में अदालत 18 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने कहा था कि वह आयुक्त की नियुक्ति और सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर सोमवार को फैसला करेगी।

महिला को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने पर भड़के जेपी नड्डा, कछा-कांग्रेस सरकार के सत्ता में महिलाएं सुरक्षित नहीं है

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाए जाने की घटना की आज कड़ी निंदा की और कहा कि यह मामला इस तरह के अपराधों से निपटने में कांग्रेस की सरकारों के 'गैरजिम्मेदाराना व्यवहार को भी उजागर करता है। नड्डा ने इस घटना की विस्तार से जानकारी हासिल करने और केंद्रीय नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक पांच सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल का भी गठन किया। इस दल में पार्टी की चार महिला सांसद अपराजिता सारंगी, सुनीता दुगल, लॉकेट चटर्जी, रंजीता कोली और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर के घुमाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। बयान के मुताबिक नड्डा ने कहा, "कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध नियमित अंतराल पर हो रहे हैं। यह इस तरह के अपराधों से निपटने में देश में हर जगह कांग्रेस सरकारों के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार को भी उजागर करता है। पार्टी की ओर से बताया गया कि पांच सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल जल्द से जल्द घटनास्थल का दौरा करेगा और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगा। बेलगावी जिले के एक गांव में पिछले दिनों एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने की घटना सामने आई थी। पीड़ित महिला का बेटा 11 दिसंबर की तड़के उस लड़की के साथ भाग गया था जिसकी सगाई किसी और से होने वाली थी। इसके बाद महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसे निर्वस्त्र कर घुमाया गया और बिजली के खंभे से बांध दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को मीडिया में आई कुछ खबरों के आधार पर घटना का स्वरूप संज्ञान लिया था और इसे 'असाधारण मामला' बताते हुए नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए थे।



पटना के दानापुर कोर्ट में शूटआउट, पेशी पर आए अपराधी की गोली मारकर हत्या

पटना। बिहार की राजधानी पटना से ससस्त्रीखेज खबर सामने आई है। यहां के दानापुर की कोर्ट कैपस में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपराधी का नाम छोट्टे सक्करा है। उसे बेजुर जेल से पेशी के लिए दानापुर कोर्ट लाया गया था। पुलिस ने मामले में दो हथियारों को कोर्ट कैपस से ही गिरफ्तार किया है। दानापुर कोर्ट शूटआउट पर सिटी एसपी गजेश कुमार का कहना है कि मृतक एक खूंखार अपराधी था। दानापुर कोर्ट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मौजूद वकीलों ने दोनों बदमाशों को फकड़स पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से दो पिस्टल काबूद की हैं। पुलिस बदमाशों हिरासत में लेकर थाने गई, जहां बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। आखिर क्यों बदमाशों ने पेशी पर आए कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक, जिस समय कैदी छोट्टे सक्करा को पेशी पर कोर्ट लाया जा रहा था, उसके साथ में 5 पुलिसकर्मी थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में भी दिनदहाड़े दोनों बदमाशों ने छोट्टे सक्करा पर 6 राउंड फायरिंग की।

सन्दावली गोल्ड

हिन्दी

पाइडर

Sandauli Gold Detergent Powder

खुशबूओं से भरपूर...

Manufactured By: SRI HARIVANSH ENTERPRISES Sandauli Unnarp School, Sandauli - 225003 (U.P.)

विश्वास करेंगे एक बार, इस्तेमाल करेंगे बार बार..!

Filter Protection Technology Removes dirt from clothes

Stain Fighter Removes dirt and stains

Colour Protection with New Colour Fixer Technology Prevents colour fading

Grease Fighter Removes grease and oil stains

सन्दावली गोल्ड

हिन्दी

पाइडर

प्रयाग दर्पण

समझौते की सार्थकता

विश्वव्यापी जलवायु संकट के बीच दुर्बुई में आयोजित जलवायु परिवर्तन केंद्रित सीओपी-28 में भले ही कोई क्रांतिकारी फैसला ग्लोबल वार्मिंग तापमान को नियंत्रण के बाबत न लिया जा सका हो, लेकिन दुनिया के लगभग दो सौ देश जीवाश्म ईंधन, मसलन कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल धीरे-धीरे खत्म करने पर जरूर राजी हुए हैं। हालांकि, अभी भी तमाम विकासशील देशों में कई तरह की चिंताएं हैं कि समझौते के व्यापक प्रावधान क्या होंगे और उनकी आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं का मुकाबला कैसे होगा। लेकिन इसके बावजूद सम्मेलन में किसी मुद्दे पर सहमति बनना एक उम्मीद जरूर जगाती है। कुछ देश उम्मीद लगाए बैठे थे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को खत्म करने के लिए किसी समथबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। वे इस बदलाव की राह में आगे बढ़ाने के वायदे से संतुष्ट नजर नहीं आए। विडंबना यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित इस जलवायु सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन को खत्म करने का विरोध ओपेक देशों के सदस्य भी कर रहे थे। वैसे भी जीवाश्म ईंधन से अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलाने वाले देशों से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके विपरीत तेल उत्पादक देश कार्बन जमा करने की तकनीकों को बढ़ावा देने पर बल देते रहे। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि दुनिया के संपन्न देश जीवाश्म ईंधन समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करें, लेकिन वैया होता नजर नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि ताकतवर राष्ट्रों ने दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन करके अपना औद्योगिकीकरण किया। निस्संदेह, उसकी ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका रही है। जब विकासशील देशों के विकास ने गति पकड़ी तो उन्हें पर्यावरण संकट पर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने से रोका जाने लगा। ऐसे समय पर जब पश्चिमी देश पहले ही अपने जीवाश्म ईंधन का अधिकतम उपयोग कर चुके हैं, विकासशील देशों के साथ बाध्यकारी शर्तें अत्यवपूर्ण ही कही जाएंगी। दरअसल, इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि क्षतिपूर्ति के तौर पर विकसित देश विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने को राजी नहीं हुए हैं। तीसरी दुनिया के देश जीवाश्म ईंधन के विकल्प में जिस नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, उसके संबल को दी जाने वाली रकम बेहद कम है। इसके किमये सत्तर कंटाई डॉलर का फंड नाकामि है। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की लड़ाई में दुनिया के गरीब मुल्कों को बड़ी पूंजी की जरूरत होगी। कहा जा सकता है कि दुर्बुई में संपन्न पर्यावरण सम्मेलन उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा है, जहां तक पहलूने की उम्मीद लगाई गई थी। सम्मेलन की सफ़्ता इस बात पर निर्भर करती कि विकासशील व गरीब मुल्कों को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिस्थापन के लिये कितनी ठोस आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन देशों की मदद के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कोई ठोस प्रयास नहीं किये जो ग्लोबल वार्मिंग के चरम का सामना करते हुए, पर्यावाह आर्थिक संकट से जुझ रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्क बाढ़ व सूखे की श्रावसी डेल रहे हैं। जिनमें उत्तरी पूर्वी अफ्रीकी देशों की स्थिति ज्यादा ही खराब है। इनमें कई देश ऐसे हैं जो कई सालों से निरंतर सूखे की भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके ग्लोबल वार्मिंग संकट के मुकाबले के लिये विकसित देशों व दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी को ठोस प्रयास करने की जरूरत है, ताकि भूख व विस्थापन के संकट का मुकाबला किया जाए। दुनिया की खाद्य शृंखला को बचाने की भी सख्त जरूरत है। साथ ही उन सस्ती तकनीकों व उपकरणों की जरूरत गरीब मुल्कों को है जो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तीन गुना बढ़ाने में सहायक हों। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका निभाने वाली मीथेन गैस का उत्सर्जन कम करना भी हमारी प्रार्थमिकता होनी चाहिए। यह सुखद है कि तीन दर्जन से अधिक गैस-तेल उत्पादक कंपनियां मीथेन उत्सर्जन कम करने पर सहमत हुई हैं। साथ ही मानवता की रक्षा के लिये ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव से बढ्ने वाली बीमारियों पर नियंत्रण व प्रभावित देशों की मदद की भी जरूरत है।

धुएं और नारों पर मौन मोदी

बुधवार को भारत के नये संसद भवन में घुसकर धुंआ फैलाने और बाहर नारेबाजी करने के पीछे जो लोग हैं, उनमें से चार को पकड़ लिया गया है तथा कुछ की तलाश जारी है। इनसे पूछताछ से मुख्‍यतः जो बात सामने आई है, उससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि उनका मकसद कोई बड़ी घटना को अंजाम देना नहीं था, वरन जमात की कतिपय समस्याओं की ओर देश की सबसे बड़ी पंचायत का ध्यान आकृष्ट करना था। यह तो माना जा सकता है कि युवाओं द्वारा अपनी बात को थोड़ा समसनीयता के तरे से प्रकट उठया गया है, लेकिन इसके अरक्‍स दो बातें सामने आई हैं-पहली तो यह कि करोड़ों रुपयों से निर्मित नये संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्‍था अत्यंत लचर है; और दूसरी बात है प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की हमेशा की भांति चुपगी। इस हादसे ने साबित कर दिया है कि देश के साथ बड़ी से बड़ी बात हो जाये, मोदी अपना मौन बत कर्त्त नहीं तोड़ेगें। यह दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं वरन एक हद तक शर्मनाक भी है।नया संसद भवन मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। देश में जब कोविड-19 का भीषण प्रकोप था तथा देश को महामारी से लड़ने के लिये बड़ी धन राशि की आवश्यकता थी, तब इसका निर्माण किया गया था। मोदी खुद इसकी प्रगति देखने आते रहते थे। उस समय इस बात का यह कहकर विरोध हुआ था कि पुराने संसद भवन के रहते, वह भी ठीक-ठाक हालत में होने के बावजूद इस नये भवन को बनवाना एक बड़ी फिजूलखर्ची है। बाद में यह बात साफ होती चली गई कि इसका उद्देश्य पुराने भवन के साथ नथी देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को मिटाना है।राजकारण, उस भवन पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो सुखद छांव बनी हुई थी, वह मोदी को उनकी विचारधारा के कारण कड़ी धूप सी प्रतीत होती थी। इसी क्रम में उन्होंने नेहरू के शासकीय निवास तीन मुर्ति भवन को भी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में बदलवा दिया। नेहरू विरोध के अलावा मोदी नये भवन का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरहाल, इस भवन के बारे में दवा किया गया था कि इसकी सुरक्षा बड़ी पुख्ता है। विशेषकर 13 दिसम्बर, 2001 को पुराने भवन पर हुए आतंकी हमले के मनेज्मन्ट इसकी ज़रूरत भी थी।इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर बुलाये गये विशेष सत्र को छोड़ दे तो यही इसका नियमित सत्र (शीतकालीन) है, जो अब भी जारी है। पहले ही सत्र में, वह भी ठीक उसी दिन- 22 वर्षों के बाद इसकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल कुछ निहत्थे खुाओं ने खोलकर रख दी। उनके कृत्य को कर्त्त समर्थन नहीं मिल रहा है परन्तु इसमें कोई शक नहीं रह जाना चाहिये कि इस भवन की सजावट पर तो खूब ध्यान दिया गया है, लेकिन सुरक्षा की बुनियादी आवश्यकता पूरी तरह से नज़रअंजु की गई है। दो दशक पूर्व हुए हातले में तो जांबाज सुरक्षाकर्मियों ने आतंकवादियों को संसद भवन में घुसने तक नहीं दिया था। अबकी एक नहीं दो लोग दर्शक दीर्घा से सदन के बीचों-बीच कूट पड़ते हैं और बाकायदा एक से दूसरी बेंचों को फलाने में भी सफल हो जाते हैं।

सम्पादकीय/लेख

भारत के विकास के नए सोपान



अंतर्गत सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सराहनीय प्रगति की है वर्ष 1951 से लेकर अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी है7 वर्ष 2015 में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना की गई जो भारत को वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनाने का दिशा में सहयोग कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की खेती 1990 के पश्चात निरंतर बढ़ रही है इस दिशा में 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली उदारीकरण निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति का महत्वपूर्ण योगदान भी माना जा रहा जिस तरह डटकर मुकाबला कर उस से निजात पाने का प्रयास किया है वह अत्यंत उल्लेखनीय है।स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में नियोजन की नीति अपनाई तथा वर्ष 1951 में प्रारंभ पंचवर्षीय योजनाओं के

परिस्थितियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं विशाल जनसंख्या के उपयोग कर विश्व पटल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत की विशाल जनसंख्या को आर्थिक सफ़्ताते के मजबूत स्तंभ कहा जा सकता है। भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं विशाल जनसंख्या का उपयोग कर उत्पादन को कई गुना बढ़ाया है। आज की स्थिति में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है और इसे तथाकथित भावी विश्व शक्ति चीन का सबसे ताकतवर प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भावी सदस्य के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत में समय के अनुसार अपनी नीतियों तथा विकास के प्रति मानकों में परिवर्तन कर निरंतर आर्थिक

विकास की दर को प्राप्त करते हुए अधिकांश विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की है। वास्तव में वर्तमान समय में भारत के ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे विश्व के सभी देश किसी न किसी रूप से जुड़कर प्रभावित भी हुए हैं। 1974 उल्लेखनीय रहा है क्योंकि भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया इसका विरोध विश्व के तमाम विकसित देशों ने बहुत जोरदार ढंग से किया भारत को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। वर्ष 2008 में हमारे देश और अमेरिका रूस प्रॉस ब्रिटेन तथा चीन को छोड़कर पी5 के सभी सदस्य देशों के मध्य हुए असैन्य परमाणु सम्झौता से यह स्पष्ट हो गया था कि अब वैश्विक पटल पर भारत की अनेकड़ी नहीं के बाहर रहकर भी भारत की प्रतिािद्धि में

काँप 28 ने भले ही टकराव को टाल दिया, पर संघर्ष के बिंदु अनसुलझे रहे

के रवीन्‍द्रन

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि काँप 28 दुर्बई वैसे ही आगे बढ़ है जैसी की उम्मीद थी। चौक सदस्य देश इस बात से जुझ रहे थे कि जीवाश्म ईंधन के सबसे संवेदनशील मुद्दे को कैसे औपचारिक रूप दिया जाए और उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, इसलिए आम सहमति बनाने की कोशिश करने के लिए जलवायु शिखर सम्मेलन को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ाना पड़ा। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार काँप 28 ने अंतिम घोषणा के रूप में एक प्रस्तावित पाठ जारी किया है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफवैश्विक लड़ाई के हिस्से के रूप में देशों से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्‍वान करेगा। यह कुछ सबसे मुखर राज्यों की सफ्‍फता का प्रतीक है जिन्होंने जीवाश्म युग को समाप्त करने के संकल्प को इंगित करने के लिए मजबूत भाषा पर जोर दिया, एक ऐसा लक्ष्य जिसका तेल और कोयला उत्पादक देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा था। यह टकराव शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में ही अंतर्निहित था, उस कुर्सी पर आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के सीईओ बैठे थे। शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष सुल्तान अल जबर की एक टिप्पणी श्‍कोई विज्ञान नहीं हैशु जो यह दर्शाता है कि वैश्विक तापन को 1.5 एण तक सीमित करने के लिए जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता है, जिससे भीहैं तन गईं। वह इस हद तक दावा करने लगे कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्‍म करना टिकाऊ नहीं होगा। दरअसल, मुख्‍य शिखर सम्मेलन से इतर एक महिला-उन्‍मुख कार्यक्रम में उनके और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जहां उन्होंने कहा कि उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। ओपेक सदस्य उत्‍सर्जन को पकड़ने और संग्रहीत करने की प्रौद्योगिकियों के माध्‍यम से जीवाश्म ईंधन के बजाय

से चीन में स्‍थायी विकास, ने वैश्विक कोयला खपत को बढ़ाये रखा है। ऐसी स्थिति में कम कार्बन वाले बिजली स्रोतों के तेजी से विकास से कोयला धीरे-धीरे विस्‍थापित हो जायेगा, जिससे एक स्‍वच्‍छ, हल्‍की प्रणाली की शुरुआत होगी, जबकि एशिया में भी क्षमता में निवेश अगले कुछ वर्षों में जारी रहेगा। प्रचुर कोयला भंडार और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए ऊर्जा आपूर्ति को शीघ्रता से बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, एशिया दुनिया की तीन-चौथाई से अधिक कोयला उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र में कोयला उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है, लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच नयी परियोजनाओं की गति धीमी हो रही है। चीन, जर्मनी और अमेरिका जैसे दुनिया भर के देश जो कोयले पर अल्‍पधिक निर्भर हैं, कोयले को आसानी से विस्‍थापित करने के लिए काफी तेजी से और अनुकूल अर्थव्‍यवस्‍था के साथ नवीकरणीय क्षमता विकसित कर रहे हैं। यूरोप और उत्‍तरी अमेरिका व्‍यवस्थित रूप से कोयला उत्पादन को प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्‍वच्‍छ स्रोतों से बदल रहे हैं, जिससे 1990 के बाद से कोयला बिजली क्षमता 200 गीगावॉट से अधिक कम हो गई है। यूरोप की गिरावट मुख्‍य रूप से सख्‍त उत्‍सर्जन नीतियों से प्रेरित है, जबकि उत्‍तरी अमेरिका ने मुख्‍य रूप से कोयला उत्पादन को गैस से बदल दिया है। प्रचुर क्षेत्रीय उत्पादन के कारण बिजली की कीमतें कम हो गई हैं। एशिया ने पिछले पांच वर्षों में प्रत्‍येक में 40 गीगावॉट से अधिक नयी कोयल क्षमता जोड़ी है और अगले वर्ष 52 गीगावॉट जुड़ने की उम्‍मीद है। दूसरे शब्‍दों में, एशिया 2024 में अर्जेंटीना की कुल स्‍थापित क्षमता से अधिक कोयला क्षमता जोड़ेगा। इस नयी क्षमता का अधिकांश हिस्‍सा चीन में है, इसके बाद भारत और इंडोनेशिया का स्‍थान है। यह वृद्धि 2027 तक जारी रहने की उम्‍मीद है, हालांकि धीमी गति से, जिसके बाद कोयला बिजली संयंत्रों में गिरावट शुरु हो जायेगी।

यूजीसी और एनसीईआरटी का हिन्दू राष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम

भाजपा सरकार केन्द्र में अपनी सत्ता की दूसरी पारी के अंत की ओर है। करीब दस साल की इस अवधि में सरकार ने देश के लगभग सभी संस्थानों और संस्थाओं की दशा और दिशा में जो बदलाव किये हैं, वे सबके सामने हैं। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ वह सब कुछ किया, जो वे कर सकती थीं। कई मौकों पर चुनाव आयोग की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं रही है। इस बीच, यूजीसी और एनसीईआरटी शिक्षा णपाली और पाठ्यक्रमों में सत्ताधारी दल को सुहाने वाले परिवर्तन करने में व्यस्त रही हैं।नयी शिक्षा नीति (एनईपी) हमारी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे और स्वरूप से आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली है। सरकार द्वारा नियमित रूप से ऐसे निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनसे विद्यार्थियों के मनो-मस्तिष्क में हिन्दू राष्ट्रवादी विचार और सिद्धांत बिखरे जा सकें। सरकार ने सबसे पहले विद्यार्थियों के आंदोलनों और उनके प्रतिरोध को कमजोर करने और उनमें भागीदारी करने वालों को डराने-धमकाने का अभियान शुरू किया। इन आंदोलनों के नेताओं पर राष्ट्रद्रोही का लेबल चस्पा कर दिया गया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री सुमित ईरानी ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक बहुत ऊंचे खम्बे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। यह प्रस्तावित किया गया कि विचारहालत नेहरू

विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कैम्पस में सेना का एक टैंक स्थापित किया जाए। वह इसलिए क्योंकि वहां के विद्यार्थी ऐसे मसले उठा रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं थे।हाल में इसी तर्ज पर कई निर्देश, आदेश जारी किये गए हैं। इनमें से एक यह है कि आरएसएस के प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के संस्थापक दत्ताजी दिदोलकर की जन्म शताब्दी को मनाने के लिए एक साल तक चलने वाले आयोजनों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। एक हिन्दू राष्ट्रवादी को राष्ट्रीययक का दर्जा देने का इस प्रयास का फोकस महाराष्ट्र के कालेंजों पर है। क्या हिन्दू राष्ट्रवादी नेताओं को हीरो बनाने का यूजीसी का यह प्रयास उचित है? क्या हमें उन नायकों को याद नहीं करना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रवाद के हमी थे और जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संग्राम का नेतृत्व किया था? आरएसएस से जुड़े दिदोलकर न तो स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा थे और ना ही वे भारतीय संविधान के मूल्यों में आस्था रखते थे। यूजीसी ने एक और संकूलर जारी कर कहा है कि कौनों जनों में सेलेफे पॉइंट बनाए जाने चाहिए जिनकी प्रुष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी का चित्र हो। कहने की जरूरत नहीं कि यह 2024 के आमचुनाव की तैयारी है। किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सरकार को किसी भी एक पार्टी



के शीर्ष नेता का प्रचार करना चाहिए? क्या यह प्रजातान्त्रिक मानकों का उल्लंघन नहीं है? प्रजातान्त्रिक और संवैधानिक मूल्यों का इस तरह का खुल्लमखुल्ल मझौल क्या सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के घोर दुरुपयोग के श्रेणी में नहीं आता? इससे भी एक दमक आगे

बढ़कर, यह निर्देश जारी किया गया है कि क्या सात से लेकर कक्षा बारह तक के विद्यार्थियों को इतिहास के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में रामायण और महाभारत पढ़ाया जाना चाहिए (टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 नवम्बर, 2023)। एनसीआरटी के एक्सपर्ट

का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समय वे लिखे गए थे। हम इन महाकाव्यों से उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।रामायण भारत में ही नहीं, वरन् श्रीलंका, थाईलैंड, बाली और सुमात्रा सहित एशिया के कई देशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। रामायण के कई अलग-अलग संस्करण हैं। रामायण के मूल लेखक सांस्कृतिक थे। गोस्वामी तुलसीदास ने जनभाषा अवधी में उसका अनुवाद कर उसे आम जनता तक पहुंचाया। सोलहवीं सदी से रामायण उन्नत भारत की जन संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है। भगवान राम की वह कथा जो हिन्दू राष्ट्रवातियों को प्रिय है, इस कथा के कई अलग-अलग पाठों में से एक है। पौला रिचमेन की पुस्तक 'मेनी रामयन्स' (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), भगवान राम की कहानी के अलग-अलग संस्करणों के बारे में बताती है। ठीक-ठीक क्या हुआ था यह साफनहीं है मगर यह महाकाव्य हमें उस काल के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। उसी तरह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित विश्व की सबसे लम्बी कविता महाभारत भी हमें उस युग में झांकने का मौका देती है। ये दोनों कथ्य ज्ञान के स्रोत हैं। मगर उन्हें इतिहास के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करना एक अलग मसला है, जिसका सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद से ज्यादा और विद्यार्थियों को इतिहास के सच से परिचित करवाना कम है।यह भी कहा गया है कि

वृद्धि की है। इन उद्योगपतियों में इंदिरा नूई, अरुण सरीन, सबीर भाटिया, विनोद घोसला का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। भारत मूल के ही सलमान रश्दी लेखक, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री, झुपा लहरी लेखिका, वैकटरमन रामकृष्णन नोबेल पुरस्कार विजेता आदि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैंस वर्ष 2014 में केंद्र में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में कार्य किया है। जिसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, चीन, फ़्रांस और अफ्रीकी देशों के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है, जिससे अमेरिकी विलेखकों के मन में भय पैदा हो गया हैस भारतीय औद्योगिक घराने अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी कंपनियों को खरीद कर दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी समूह बन गए हैं। भारत लक्ष्मी मितल विश्व के सबसे बड़े स्टील उत्पादक है, मुकेश अंबानी का नाम विश्व के सर्वोच्च पांच धनी व्यक्तियों में लगातार प्रत्येक और शामिल होता रहा है। टाटा स्टील ने अपने आकार से लगभग 6 गुनी बड़ी कंपनी कोरस को भी खरीद लिया तो दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड जगुआर लैंडरोवर को खरीद कर इसे ड.उ. की प्रतिभागीता में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय मूल के विदेशी उद्योगपतियों ने भारत के बाहर रहकर भी भारत की प्रतिािद्धि में

आज का राशि फल					
मे़ष	वृ़ष	मि़थुन	कर्क़	सिंह	कन्या
तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
<p>मे़ष:- किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुःखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कर्दां न करें।</p> <p>वृ़षभ:- भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओ द्वारा महत्वपूर्ण कार्यरों को समायनुकूल पूर्ण करेंगे।</p> <p>मि़थुन :- भावनाओं पर नियंत्रणरख अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा-प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।</p> <p>कर्क़ :- महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक-सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।</p> <p>सिंह :- भावना से उद्बलित मन निकट संबंधों के सुख-दुःख के प्रति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहस्व संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी क्षमता को गैस से बदल दिया है। प्रचुर क्षेत्रीय उत्पादन के कारण बिजली की कीमतें कम हो गई हैं। एशिया ने पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक में 40 गीगावॉट से अधिक नयी कोयल क्षमता जोड़ी है और अगले वर्ष 52 गीगावॉट जुड़ने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, एशिया 2024 में अर्जेंटीना की कुल स्थापित क्षमता से अधिक कोयला क्षमता जोड़ेगा। इस नयी क्षमता का अधिकांश हिस्सा चीन में है, इसके बाद भारत और इंडोनेशिया का स्थान है। यह वृद्धि 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि धीमी गति से, जिसके बाद कोयला बिजली संयंत्रों में गिरावट शुरू हो जायेगी।</p>					

तुला:- कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगीं। शासन-सत्ता की दिशा में केन्द्रित लोगों को लक्ष्य के अक्सर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिक:- किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति होगी। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगीं। भावनाप्रधान मन रिशतों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनु:- रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं साधक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती है। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्बलित करेंगीं।

मकर:- सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ:- पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन-सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा-पाठ में पूरा दिन मन केन्द्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीन:- पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि 'चुंकि हमारे देश को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था और वह गुलामी का प्रतीक है। इस तथ्य को जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि हमारे देश के लिए इंडिया से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों के भारत आने से बहुत पहले से हो रहा है। ईसा पूर्व 303 में मेगस्थनीज ने इस देश को इंडिका बताया था। सिन्धु नदी के नाम से जुड़े हुए शब्द भी लम्बे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे संविधान में प्रयुक्त वाक्यांश भारत देव इज इंडिया का कोई जवाब नहीं है। मगर हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा के चलते इंडिया शब्द उन्हें असहज करता है वे भारत के इतिहास को नए सिरे से कालखंडों में विभाजित करना चाहते हैं। इतिहास के सबसे पुराने कालखंड, जिसे अंग्रेज हिन्दूकाल कहते हैं, को वे क्लासिक (श्रेष्ठ या उत्कृष्ट) काल कहना चाहते हैं। उद्देश्य है इस कालखंड में प्रचलित मूल्यों को हमारे समाज के लिए आदर्श नियत करना। ये मूल्य, जो मनुस्मृति में वर्णित हैं, वही हैं जिनके विरुद्ध अम्बेडकर ने विद्रोह का झंडा उठाया था और मनुस्मृति का दहन किया था।आज यूजीसी और एनसीईआरटी का मार्गदर्शक केवल और केवल हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा है। भारतीय संविधान के मूल्यों से उन्हें कोई लेनादेना नहीं है।-**राम पुनिया**नी

भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जरूरी है मोदी की गारंटी: शर्मा

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। प्रधानमंत्री के संकल्प व प्रेरणा से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने तथा सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रदेश की योगी सरकार प्रयास कर रही और मोदी के संकल्प ‘सबका साथ, सबका विकास’ के साथ कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों, वंचितों, महिलाओं, असहयोग, किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। इसी संकल्प की पूर्ति हेतु ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं से जोड़ने के साथ शहीदों के प्रति श्रद्धाभाव व राष्ट्रभे्र को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको सरकारी योजना का लाभ भी दिलाया जा रहा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शुक्रवार को सिद्धार्थनगर जनपद की इटवा विधानसभा के धनवापुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत जिला हजीबपुर पहुंचकर वहां पर ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के तहत आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विकसित भारत

पुल की रेलिंग तोड़ खाई में गिरी रोडवेज बस, दो लोगों की मौत

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग तुलसीपुर स्थित लोकहवा गांव के पास सुबह करीब 5.30 बजे यात्रियों से भरी रोडवेज बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे खाई में पलट गई। दुर्घटना में पचपेड़वा के ओरहवा गांव निवासी 22 वर्षीय दिलीप प्रजापति पुत्र संतोष कुमार समेत दो यात्रियों की मौत हो गई।चालक संतोष कुमार सैनी व परिचालक मक निवासी सूरज व नेपाली यात्री समेत 18 लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला मेमोरियल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में भर्ती करया गया है। चालक संतोष की हालत नाजुक होने पर बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।बलरामपुर डिपो की बस संख्या यूपी 47 टी 2648 गुरुवार रात करीब 11 बजे कैसरबाग लखनऊ से बढनी के लिए चली थी। सुबह करीब पांच बजे बलरामपुर में यात्रियों को उतारने के बाद बस बढनी के लिए निकली। बस में 36 यात्री सवार थे। राष्ट्रीय राजमार्ग तुलसीपुर स्थित लोकहवा गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पुल की

टक्कर मारने के बाद बस चालक भाग निकला था, पुलिस की दो टीमें कर रही थी तलाश

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बीती गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो फुटेज में एक दम साफ़ दिखाई दे रहा है कि सभा खेड़ा गांव की ओर से एक सफेद रंग की कार मुड़ती है और इसी बीच स्कूटी सवार महिला कार से बचने के चक्कर में बस की ओर से आई और स्कूटी सवार महिला और उसमें बैठे दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस और कार चालक दोनों ही अपने बचन लेकर निकल जाते हैं। पीजीआई पुलिस ने शुक्रवार को सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई बस को अपने कब्जे में लेकर पीजीआई कोतवाली में खड़ा करवा कर उसके चालक की जानकारी कर रही हैं।पुलिस के



संकल्प यात्रा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर आदिवासी दिवस के दिन बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी दिलाना है। इस संकल्प यात्रा के तहत गांव-नगरों में पहुंच रही ‘मोदी की गारंटी वैन’ देश के हर नागरिक के जीवन में सुखा, समृद्धि और खुशहाली का वाहक बन गई है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों गांव-गांव, शहर-शहर में करोड़ों लोगों को इस यात्रा के माध्यम से जोड़ा गया और पात्रों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने

कहा कि देश में मोदी की गारंटी के अलावा कोई और गारंटी नहीं चलेगी। ईंजे 70 वर्षों में नहीं हुआ व मोदी और योगी के नेतृत्व में हो रहा है और आज हम लोकतंत्र के स्वर्णकाल में जी रहे हैं। पहले लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता था, आज गरीबों के पेट में जा रहा। कम लागत, कम ख़ाद व दवाई ख़ालकर किसान नैनो यूरिया का प्रयोग कर अच्छे पैदावार कर सकते हैं। देश में गरीबों की आमदनी कैसे बढ़े, हर व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, सभी को अच्छी शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, सुखा, अच्छी सड़कें हों, मोदी का यही संकल्प है। मोदी ने देश को विश्व की 10वें नम्बर की अर्थव्यवस्था से मिलेगा। पिछली सरकारें चन्दयान नहीं बना सकती थीं, शौचालय तो बना ही सकते थे।

राम मंदिर के 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत,हैदराबाद के कारीगरों की नक़्क़ाशी

प्रयाग दर्पण संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे होंगे। इसमें से 18 दरवाजे ग्राउंड फ्लोर पर लंगेंगे। इन 18 में से 14 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ेगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सांगौन की खास लकड़ी से बने इन दरवाजों पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक़्क़ाशी की है। इसके बाद इन पर तांबे की परत चढ़ाई गई। अब इस पर सोने की परत लगाने का काम जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले अयोध्या में एक महायज्ञ भी शुरू हुआ है। जो प्राण प्रतिष्ठ तक लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठ में कोई व्यवधान न आए। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहां लगने वाले 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजों की जिम्मेदारी गाजियाबाद की एक ज्वेलर्स कंपनी को दी गई है। सुर्जों के अनुसार, 7 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ा दी गई है। जनवरी के पहले सप्ताह तक सभी दरवाजें तैयार हो जाएंगी। इसी तरह राम मंदिर के गर्भगृह का सिंहासन भी बनकर तैयार हो चुका है। यहां भी सोने का काम होना बाकी है। श्रीरामचमपूति तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठ से पहले होने वाले सभी निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक पूरे कर लिए जाएं। बचे हुए कामों को हर हाल में जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यों की समीक्षा शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठ के मौके पर अयोध्या आने वाले रामभक्तों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 25 दिसंबर से 15 मार्च तक अयोध्या में 36 स्थान पर भंडारे चलेंगे। इसके लिए देशभर से राम

देश की 9.2 प्रतिशत की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नम्बर पर ला दिये हैं जबकि गुजरात की अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत है। मोदी के नेतृत्व में जिस प्रगति से देश आगे बढ़ रहा, इससे पूरी दुनिया अर्चनित है। किसी भी परिस्थिति व संकट पर पूरा विश्व आज मोदी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा। पूरी दुनिया में भारत देश और भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है। देश के 85 करोड़ गरीबों को मुश्किलों से बचने के लिए मोदी सरकार द्वारा आगे भी 05 वर्षों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी का सिर्फ एक ही सपना है कि ऐसा विकसित भारत बने, जिसमें हर स्तर पर बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर मिले, चारों ओर खुशहाली हो, कोई भी अपने जीवन में दीन दुःखी, गरीब और लाचार न रहे। अर्थात् ‘नहिं दरिद्र कोऊ दुःखी न दीना, नहिं कोऊ अबुध न लच्छन हीना’ को चरितार्थ करने तथा मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन दीजिए। हमारी परिस्थितियां कुछ भी हों, मगर हमें बड़ा सपना देखना चाहिए और उसके लिए कार्य भी करना चाहिए। जब सही रथ चुनेंगे तभी सही रथी उठकर चौथे-पांचवें नम्बर पर ला दिया है। योगी ने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र के बाद पूरे



भक्त अनाज और मसाले लेकर आ रहे हैं। अयोध्या में असम से चार पत्ती, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक की पहली खेप आ चुकी है। हरियाणा से 400 क़िंटल चावल अयोध्या पहुंच चुका है। गो़डा से चीनी भेजी गई है। रामसेवक पुरम में केंद्रीय भंडार गृह बनाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की 4 नई तस्वीरें सामने आई हैं। शुक्रवार को श्रीरामचमपूति तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी की हैं। पहली तस्वीर में राम मंदिर की छत पर काम किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में मंदिर के अंदर मंडप की है। जिसमें बेहतरन नक़्क़ाशी की गई है। तीसरी तस्वीर में राम मंदिर में दर्शन मार्ग की तर्फ बन रहे गेट की है। वहीं चौथी तस्वीर को ज़ेन से ली गई है। जिसमें राम मंदिर के छत पर काम होता दिख रहा है।

मिल्लीपुर में 1500 छात्रों को नहीं मिला ड्रेस का पैसा

अयोध्या। जिले में मिल्लीपुर के परिषदीय स्कूलों के करीब 1500 छात्र छात्राओं के खाते में डायरेक्ट बेंनेफिट ट्रांसफर योजना के तहत पैसे नहीं भेजे जा सके। डीबीटी योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जूता-मोजा, ड्रेस व स्कूल बैग के लिए सरकार द्वारा 1200 रुपए की धनराशि दी जाती है। यह पैसा सीधे छात्रों के अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। मिल्लीपुर क्षेत्र के 598 परिषदीय स्कूलों में वर्तमान में करीब 49,837 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। करीब 48,373 हजार छात्र-छात्राओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि आधार कार्ड में जुटि होने के कारण करीब 1500 छात्र इससे वंचित रह गए हैं। बताया जाता है कि इन बच्चों के नाम तो कहीं माता-पिता का नाम या पता आदि गलत फ़ीड हो गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह जुटि अभिभावकों को लापरवाही के चलते हुई है, साथ ही वह इसे ठीक कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि अभिभावकों द्वारा छात्राओं के आधार कार्ड की त्रुटियों को ठीक नहीं कराया गया चुनावों और उपेक्षा से किसान बेहाल है। किसानों के लिए खेती घाटे का सीधा बनकर रह गयी है। धान, गन्ना, गेहूं, मूंगफली, आलू सभी फ़सलों के किसान परेशान है। बढ़ती महंगाई के चलते किसानों को फ़सलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अखिलेश

भाजपा सरकार की गलत नीतियों और उपेक्षा से किसान बेहाल: अखिलेश यादव



प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और उपेक्षा से किसान बेहाल है। किसानों के लिए खेती घाटे का सीधा बनकर रह गयी है। धान, गन्ना, गेहूं, मूंगफली, आलू सभी फ़सलों के किसान परेशान है। बढ़ती महंगाई के चलते किसानों को फ़सलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अखिलेश

छात्रा से रेप,घर लौटते समय युवक ने की दरिंदगी, पीड़िता ने बाइक के नंबर से पकड़वाया

गोण्डा। जिले में एक 16 साल की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। रात को घर लौट रही छात्रा के साथ युवक ने दरिंदगी की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित छात्रा का गोडा जिला महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। छात्रा के मुताबिक, बीते मंगलवार को दोर रात अपने घर आ रही थी। रास्ते में आरोपी अन्तिम सिंह ने अकेले पाकर घसीट लिया और खेत में ले जाकर दरिंदगी की। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।पीड़ित छात्रा ने आरोपी की मोटरसाइकिल का देखा लिया और घर आकर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद परिवार के साथ थाने में जाकर पीड़ित छात्रा लिखित शिकायत देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उसकी बाइक का नंबर नोट करया।परसपुर पुलिस ने पूरी मामले में टुकमंड और पाँचसौ एक्ट जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

17 दिसम्बर की रैली के लिए निकाला बाईक जूलूस

लखनऊ । अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश कार्यालय हलवासिया कोर्ट से सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुधीर एस. हलवासिया के नेतृत्व में दो पहिया वाहन रैली निकाली गयी जो हजरतगंज, जीपी.ओ. विधान सभा मार्ग, हुसैनगंज, चारबाग, नक्का बसामंडी, लाटूड रोड, गणेशगंज, कैसरबाग, लालबाग होते हुए हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट पर समाप्त हुई। समापन के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुधीर एस. हलवासिया ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा की वैश्य समाज के सभी उपवर्ग जब एक होकर वटपशु का निर्माण करते हैं तो सभी शाखाओं की शक्ति से निकला हुआ बन किसी को भी चुनौती देने के लिए तैयार रहता है, वैश्य समाज अब सड़कों पर उत्तरकर संघर्ष करने को तैयार है। हमारे अधिकारों का ख्याल सरकारों को रखना होगा। उत्तर प्रदेश में हम छह करोड़ की आबादी में निवास करते हैं हमारी आबादी के अनुरूप हमें सभी क्षेत्रों में अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी उपखलों में एक सांस्द, प्रत्येक जनपदों में एक विधायक हमारे समाज से होना चाहिए।17 दिसम्बर 2023 रविवार को चारबाग रेलवे स्टैंडियम में वैश्य समाज के चौंसिया, महानज, भाराङ्ग वैश्य, चौसैनी, चतुर्धुरी, पालीवाल, माहेधरी, जायसवाल, ऊमर, माथुर, दोसर, विजयगोपाल, मोदवाल, माहौर अयोध्यावासी, महानर, माथू, पटवा, सम्मानी, गहौड़, शिवहरे, बरनवाल, बाथम, कायस्थ, जैन, केसरवानी, अग्रवाल, ओमर, खण्डेलवाल, कसीधन कायस्थूज पुजौ, बारहसैनी, कांस्वरकार, खत्री, रौनियार, अंगार, पुवार, स्पर्णकार, रस्तोगी, राजवंशी, पोखवाल, वाण्ण्य, साहू, मधेशिया, ओनाय, गुलहरे, अग्रहरी, यज्ञसैनी उपवर्गों का संयुक्त व केन्द्रीय संघान अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सभी उपवर्गों की मांग व समस्याओं के प्रति सजग है और उनके लिए संघर्ष करने को तैयार है।

करंट से पिता- पुत्र की मौत, गेहूं की फसल की सिंचाई करते समय वॉपेट में आए

गोण्डा। जिले में परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाले सेज पिता-पुत्र की देर रात खेत की सिंचाई करते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौक पर पहुंची परसपुर पुलिस ने बाप बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच में जुटी हुई है। परसपुर थाना क्षेत्र का राजापुर ग्राम पंचायत के बलिकनपुरवा मजरे के रहने वाले 25 वर्षीय विपिन सिंह और 48 वर्षीय राघवेंद्र की देर रात करंट से मृत हो गए। पितापुत्र ने सिंह घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेत पर पंपिंग सेट से गेहूं की सिंचाई कर रहे थे। खेत के बगल लगे विद्युत पोल पर हाथ रखते ही दोनों बाप बेटे करंट की चपेट में आ गए जहां दोनों की मौक़े पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक राघवेंद्र की पत्नी रश्मिन सिंह और से बॉटिंग शुरू कराई गई है। प्रतिदिन भ्रमण के लिए डंडे से तीन सौ लोग आते जिलों के पर्यटन स्थलों का विकास कर रहा है। सोनभद्र वाराणसी से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहां पहाड़, जंगल, नदियां, झरने हैं। प्रकृति के अनेक उपहार की वजह से लोग इसे मिनी गोवा के नाम से भी पुकारते हैं। जिला मुख्यालय से

17 करोड़ से बना बाजार अफसरों की खींचातानी से धूल फांक रहा 42 दुकानों का होना है आवंटन



बहराइच। अपनी फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े इसके लिए योगी सरकार जिलों में किसान बाजार बना रही है। लेकिन कुछ अफसरों कि वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है बहराइच। यहां पिछले 7 साल से किसान बाजार बन रहा है। यह बाजार बनकर तैयार तो हैं, लेकिन आज भी वीरान पड़ा है। इस वीरान पड़े किसान बाजार को 2 साल में पूरा होना था। किसान बाजार को बनने में 6 साल क्यों लगे? ये एक सवाल है। साल 2015 में बहराइच की मंडी समिति ने बड़े जोर-शोर से मंडी परिषद, लखनऊ को प्रस्ताव दिया कि हमारे यहां के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके लिए बहराइच में ही किसान बाजार बना दिया जाए। लखनऊ मुख्यालय ने भी इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। किसान बाजार बनाने कि रही झंझी दी दी। जगह का सिलेक्शन हो गया और जनवरी, 2016 में प्रस्ताव भी पास हो गया। तय हुआ कि 2 साल में किसान बाजार बनकर तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद मंडी परिषद की निर्माण और विद्युत खंड इकाई सक्रिय हो गईं। टेंडर जारी कर काम भी शुरू करा दिया गया। लेकिन इसके बाद ही अफसरों का खेल भी शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि किसान बाजार बनाने की जगह सही नहीं है। इसके बाद प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया। लेकिन बाद में सिर्फ बेसमेंट बनाने और लागत 17 करोड़ करने की शर्त पर प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ। काफी अड़चनों के चलते 2 साल में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट 6 साल में यानी 2022 में पूरा हो पाया। सिर्फ बेसमेंट में बनकर तैयार हुए किसान बाजार में कुल 42 दुकानें हैं। साथ ही 50 कारों का पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। कस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के साथ ही विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। 11 केवी की लाइन और इसके निरीक्षण के लिए 39 लाख रुपए विद्युत विभाग में जमा किए जा चुकें हैं। पिछले करीब 8 महीने से परिसर में लगे बिजली के इन उपकरणों की रखवाली एक व्यक्ति कर रहा है। जिस पर महीने का खर्च 15 हजार सैलरी और अन्य खर्चों के साथ मिलाकर करीब 20 हजार है। दरअसल, किसान बाजार में कुल 42 दुकानें बनी हैं। एक दुकान की कीमत 30 लाख रखी गई है। ये दुकानें व्यापारियों को बेची जाएंगी, जो किसानों से उनकी उपज खरीदेंगे। इससे किसानों को बहराइच से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट पर कम खर्च के चलते उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इस बारे में जब गहनता से पड़ताल की गई।बहराइच मंडी परिषद के सचिव धनंजय सिंह इन दुकानों के आवंटन में रोड़ा बने हुए हैं। वह निर्माण खंडों (सिविल और विद्युत) से हस्तांतरण ही नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल, जिस समय किसान बाजार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय धनंजय सिंह सचिव नहीं थे। वह अभी कुछ समय पहले ही सचिव बनाए गए हैं। इसके चलते वह दुकान आवंटन की प्रक्रिया में रोड़ा हैं। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अब प्रकरण संज्ञान में आया है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान राजितराम ने बताया कि किसान बाजार बनने उम्मीद जगी हुई थी। लेकिन वह सफेद हाथी साबित हो रही है। किसान बाजार शुरू होने से काफी राहत मिलेगी।



जरूरत है। फिर भी इन चीजों के खुले में व्यापार करने पर इतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले सरकार दुकान आवंटित करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक करते हुए बुधवार

को खुले स्थानों पर मांस और मछली की बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्यमंत्री उन्हें उजाड़ने से पहले सरकार दुकान आवंटित करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक करते हुए बुधवार

को खुले स्थानों पर मांस और मछली की बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्यमंत्री उन्हें उजाड़ने से पहले सरकार दुकान आवंटित करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक करते हुए बुधवार

